चंद्र प्रकाश और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

4 अप्रैल, 2002

[मुख्य न्यायमूर्ति एस0 पी0 भरूचा, आर0 सी0 लाहोटी, एन0 संतोष हेगड़े, रूमा पाल, अरिजीत पसायत, न्यायमूर्तिगण]

*भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 141.*

*बाध्यकारी मिसाल––सिद्धांत का––तीन और दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय––न्यायाधीशों की खंडपीठ–तथ्यों को खारिज करती है, अस्थायी डॉक्टरों और चयनित डॉक्टरों के बीच परस्पर वरिष्ठता पर विवाद–तीन–न्यायाधीशों की पीठ प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से अपनी वरिष्ठता की गणना करने के लिए अस्थायी डॉक्टरों के अधिकार को बरकरार रखती है–जेएन के बाद के फैसले दो–न्यायाधीशों की पीठ बेंच ने कहा कि अस्थायी डॉक्टरों को उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता मिलती है – राज्य सरकार दो जजों की बेंच के निर्देशों पर कार्रवाई कर रही है – रिट याचिकाएं दायर की गईं – मामले को विचार के लिए पांच जजों की बेंच को भेजा गया, अभिनिर्धारित: दो–न्यायाधीशों की पीठ सही कानून नहीं बनाती है, जब तीन न्यायाधीशों की पीठ के बीच मतभेद हो—दो न्यायाधीशों की पीठ को तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का पालन करने के लिए।*

अस्थायी डॉक्टरों और लोक सेवा आयोग (पीएससी) के माध्यम से नियुक्त चयनित डॉक्टरों के बीच अस्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता की गणना करने की कक्षा के रूप में उनके अधिकार को बरकरार रखा। बाद के फैसले में, 2–न्यायाधीशों ने कहा कि नियुक्ति नियमों के विरुद्ध वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं देती है और अस्थायी डॉक्टरों ने नियमितीकरण नियमों के अनुसार अपनी नियमित नियुक्ति की तारीख से ही अधिकार प्राप्त किया। इसके बाद, प्रतिवादियों ने दो–न्यायाधीशों द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर परिणामी कार्रवाई की। इसलिए वर्तमान रिट याचिका जिसे पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए संदर्भित किया गया है।

इसलिए वर्तमान रिट याचिका जिसे पांच जजों की बेंच को विचार के लिए भेजा गया है। विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह तीन जजों वाली बेंच और दो जजों वाली बेंच के फैसले के बीच टकराव के अस्तित्व, ऐसे टकराव के प्रभाव, यदि कोई हो, और क्या रिट याचिकाओं पर अंतिम रूप से इस बेंच द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए या नहीं, के संबंध में है। .

प्रश्न का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया: 1. जबकि तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने एक वर्ग के रूप में अस्थायी डॉक्टरों के अधिकार को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता की गणना करने का अधिकार बरकरार रखा, बाद के फैसले से दो–न्यायाधीशों की पीठ ने यह मानते हुए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया कि अस्थायी नियुक्त व्यक्ति

अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता बी का दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे केवल उसी से गिन सकते हैं

2.1 नियमितीकरण नियमों के तहत उनके नियमितीकरण की तिथि। यह अस्थायी डॉक्टरों और चयनित डॉक्टरों के बीच विवाद में शामिल मुख्य मुद्दा है, दो–न्यायाधीशों की पीठ ने तीन–न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सीधे तौर पर विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया है। बाध्यकारी मिसाल के सिद्धांत के सिद्धांत अब मौजूद नहीं हैं

2.2 यह इस न्यायालय द्वारा तय किए गए बड़ी संख्या में मामलों में परिलक्षित होता है। इस न्यायालय के अधिकांश निर्णय न केवल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पक्षों के अधिकारों पर एक निर्णय का गठन करते हैं और उनके बीच विवादों को हल करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि ऐसा करने में वे भविष्य के मामलों में एक बाध्यकारी सिद्धांत के रूप में कार्य करने वाले कानून की घोषणा को मूर्त रूप देते हैं। हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रशासन में बाध्यकारी मिसाल का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न्यायिक निर्णय में निश्चितता और निरंतरता को बढ़ावा देता है। न्यायिक स्थिरता व्यवस्था में विश्वास को बढ़ावा देती है, इसलिए,

2.3 इस न्यायालय के निर्णयों में कानूनी सिद्धांतों के प्रतिपादन में निरंतरता की आवश्यकता है। रघुबीर सिंह और परीजा के मामले में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए* यह माना जाता है कि इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय, जैसा कि उसी पीठ के बाद के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है, सही कानून नहीं बनाता है, जो कि विरोधाभासी है। तीन जजों की बेंच का फैसला। इसलिए, इन रिट याचिकाओं को अंतिम निपटान के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

*भारत संघ और अन्य। आदि बनाम रघुबीर सिंह (मृत) एलआर द्वारा। आदि, [1989] जी 2 एससीसी 754 और प्रदीप चंद्र पारिजा और अन्य। वी. प्रमोद चंद्र पटनायक और अन्य, [2002] 1 सेकंड, पर निर्भर।*

*यूपी राज्य और अन्य. बनाम डॉ. एम.जे. सिद्दीकी और अन्य, [1980] 3 एससीसी 174, संदर्भित।*

*सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 1998 की 43।*

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।)

साथ

रिट याचिका (सिविल) संख्या 237, 220, 276, 532, 539, 547/98, 176, 229 और 299/99 और अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 1, 2 और 5 से 24।

सी.एस. वैद्यनाथन, रंजीत कुमार, वी.ए. मोहता, सुबोध मार्कंडेय, पी.बी. मेनन, डॉ. जे.एन. दुबे, पी.एस. मिश्रा, ए. शरण, सुधीर चंद्रा, एम.सी. ढींगरा, विनोद शुक्ला, राजीव शर्मा, वरुण गोस्वामी, राजीव शर्मा, मो. तैयब खान, शकील अहमद सैयद, जीतेंद्र मोहन शर्मा, के.के. मोहन, मोहन बाबू अग्रवाल, करनालेन्द्र मिश्र, कु.फिरोज़ा बानो, कु. चित्रा मार्कंडेय, आर.सी. वर्मा, अशोक के. श्रीवास्तव, पुनीत कुमार सक्सैना, सीसुश्री विजयालक्ष्मी मेनन, रानी छाबड़ा के लिए अनुराग दुबे, सी.डी. सिंह, एस.चन्द्रशेखर, डॉ. एल.पी. सिंह, अनिप सच्ते, समीर अली खान, अमित के कुमार, प्रवीण स्वरूप, एस.के. वर्मा, प्रशांत चौधरी, सुश्री गीतांजलि मोहन, राजीव के. गर्ग, अभिषेक सोनी, एन.एस. गहलोत, प्रकाश सिंह, प्रनोंद स्वरूप, सुश्री मृदुला राय भारद्वाज, अरविन्द क्र. शुक्ला, अरविन्द कुमार साहू, डी राशिद सईद, इरशाद अहमद, पार्थप्रतिम चौधरी, संजीव बंसल, के.एस. राणा, आर.के. बंसल, श्रीश कुमार मिश्रा, विश्वजीत सिंह, प्रशांत कुमार, जोसेफ पुक्कट, प्रसेनजीत केसवानी, सुश्री बेला माहेश्वरी, ई.सी. विद्या सागर, (एनपी), जीवन सिंह और के.के. मोहन उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

**न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े द्वारा**: इस न्यायालय की 3–न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 17.8.2000 के एक आदेश द्वारा उपरोक्त रिट याचिकाओं को निम्नलिखित आदेश द्वारा पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार के लिए भेजा:

> "हमने विद्वान वकील को सुना है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इन मामलों को सुना जाना चाहिए और उनका निपटारा किया जाना चाहिए पाँच विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ और, जहाँ तक संभव हो, शीघ्रता से।"

इस मामले के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

> यूपी प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) में काफी लंबे समय से नियमित नियुक्तियां नहीं की गई थीं और डॉक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से अस्थायी आधार पर नियुक्तियां की जा रही थीं। ये नियुक्तियाँ दशकों तक बिना किसी रुकावट के जारी रहीं। 1979 में, प्रत्यार्थी–राज्य ने यूपी तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण (लोक सेवा आयोग के दायरे में पद पर) नियम, 1979 (संक्षेप में 'नियमितीकरण नियम') की घोषणा करके इन अस्थायी डॉक्टरों की सेवाओं को नियमित करने का दावा किया था। ), और इन नियुक्तियों को नियमों के तहत उनकी ऐसी नियमित नियुक्ति की तारीख से ही वरिष्ठता देने की मांग की।

इस बीच, वर्ष 1972 में लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों के अनुसार, उक्त आयोग ने पीएमएस में रिक्तियों को भरने के लिए चयन किया और कुछ चयनितों के नामों की सिफारिश की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के चयन और सिफ़ारिशें वर्ष 1972 और 1979 के बीच किश्तों में की गई थीं। लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए ये चयन मूल रूप से राज्य सरकार को स्वीकार्य नहीं थे, लेकिन जब वे कुछ न्यायिक घोषणाओं या अन्यथा के कारण स्वीकार्य हो गए, तो सवाल उठता है। मूल रूप से नियुक्त अस्थायी डॉक्टरों और लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त डॉक्टरों के बीच परस्पर वरिष्ठता उत्पन्न हुई। अस्थायी डॉक्टरों का यह रुख था कि उन्हें पीएससी के परामर्श से स्थायी रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था और लंबे समय तक सेवा में रहने के बाद, उनकी मूल नियुक्तियों को नियमित माना जाना चाहिए और उन्हें वरिष्ठता दी जानी चाहिए। उनकी प्रारंभिक

नियुक्तियों की तारीख. अस्थायी डॉक्टरों का यह दावा खारिज होने पर तीन अस्थायी डॉक्टरों ने तीन अलग–अलग रिट याचिकाओं में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया; सिविल विविध. डॉ. एचसी माथुर द्वारा दायर डब्ल्यूपी नंबर 20408/88 ऐसी ही एक याचिका थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.4.1991 द्वारा तीन याचिकाओं को जोड़ते हुए, अस्थायी डॉक्टरों के दावे को बरकरार रखा और माना कि उनकी वरिष्ठता की गणना पीएमएस कैडर में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए और वे भी इसके हकदार हैं। उनकी वरिष्ठता तय करने के बाद उन्हें मिलने वाले सभी सेवा लाभ दिए जाएंगे।

यूपी राज्य ने चुनिंदा रूप से डब्ल्यूपी संख्या 20408/88 में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक एसएलपी दायर की, जो डॉ. एचसी माथुर के मामले में है। उक्त मामला इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सी) संख्या 13840/92 में इस न्यायालय की 3–न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आया, जिसने अपने आदेश दिनांक 24.11.1992 द्वारा इस प्रकार कहा:

> "हमने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री डीवी सहगल को सुना है। इस विशेष अनुमति याचिका में प्रत्यार्थी ने 30 वर्षों से अधिक समय तक उत्तर प्रदेश राज्य में सेवा की है, और 20 वर्षों से अधिक समय बिताने के बाद उन्हें नियमित किया गया था। सेवा। उत्तर प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों के विनियमन (लोक सेवा आयोग के दायरे में पदों पर) नियम, 1979 पर भरोसा करते हुए, यूपी राज्य ने उन्हें वरिष्ठता के लिए 20 साल की सेवा का लाभ देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें वरिष्ठता के लिए पूरी अवधि का लाभ दिया। हमें उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमजोरी नहीं दिखती। हम तर्क और उसमें पहुंचे निष्कर्षों से सहमत हैं। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।"

इस प्रकार, अस्थायी डॉक्टरों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता की गणना करने के अधिकार को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि हुई। यह रिकॉर्ड में है कि इसके बाद कई अन्य समान रूप से स्थित अस्थायी डॉक्टरों ने भी इसी तरह की याचिकाएं दायर कीं और इसी तरह की राहत प्राप्त की, जिनमें से कुछ मामले यूपी राज्य द्वारा इस न्यायालय में लाए गए जैसे कि WP संख्या 6227/81 में निर्णय लिया गया था। इस न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) सीसी संख्या 18791/92 में जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले की 21.1.1993 को इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा फिर से पुष्टि की गई थी।

उपरोक्त कुछ याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि कुछ चयनित डॉक्टरों को, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, उन्होंने राज्य सेवा न्यायाधिकरण से यह निर्देश देने की मांग की कि उन्हें तदनुसार सेवा में नियुक्त किया जाए। लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयनों और सिफारिशों के साथ। उन याचिकाओं पर अधिकरण ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> "संदर्भों की अनुमति है, यूपी राज्य का वह आदेश जिसके तहत उसने लोक सेवा आयोग, यूपी द्वारा प्रस्तुत चयन सूची को रद्द कर दिया है, जो जीओ संख्या ।355/बाल. 4–546/78 दिनांक 13.3.84 में निहित है, को रद्द किया जा रहा है अवैध, निष्क्रिय, शून्य और शून्य और याचिकाकर्ताओं को आयोग की उक्त चयन सूची के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों के रूप में निर्णय के निकाय में उल्लिखित अन्य विचारों के अधीन नियुक्त होने और सभी परिणामी सेवा लाभ प्राप्त करने का हकदार घोषित किया जाता

है। विपक्षीगणों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय के तीन माह के भीतर 23.12.1997 की चयन सूची के आधार पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करें और सभी परिणामी सेवा लाभ भी दें।"

यूपी राज्य ने अधिकरण के उक्त आदेश को रिट याचिका संख्या 7066/86 के माध्यम से चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने अन्य संबंधित मामलों के साथ सुना, और उच्च न्यायालय ने अधिकरण के आदेश को निम्नलिखित शर्तों में संशोधित किया:

"इन परिस्थितियों में, दावा न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश पूरी तरह से उचित थे। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भर्ती लगभग 14 साल पहले की गई थी और जिन व्यक्तियों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, उन्हें पिछले 12 वर्षों के दौरान नियमित किया गया है, यह हो सकता है इस स्तर पर सभी चयनितों की नियुक्ति का निर्देश देना उचित नहीं होगा। हालांकि, याचिकाकर्ता का दावा है कि जो चयनित हो चुके हैं और तदर्थ आधार पर काम भी कर रहे हैं, उन्हें उस तारीख को नियुक्त माना जाएगा जब रिक्तियां पहली बार भरी गई थीं। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के आधार पर नियमितीकरण और तदनुसार वरिष्ठता और अन्य लाभों का हकदार होगा। अधिकरण द्वारा दी गई राहत उस सीमा तक संशोधित मानी जाएगी।"

उपरोक्त कार्यवाही से यह पता चलता है कि अधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष उन मामलों में शामिल मूल प्रश्न याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी न करने में राज्य सरकार की ओर से निष्क्रियता/इनकार के संबंध में था। उन चयनित डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी करने में सरकार की कथित निष्क्रियता पर विचार करते हुए, अधिकरण ने माना कि वे डॉक्टर उनके द्वारा मांगी गई राहत के हकदार थे। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अधिकरण के उक्त आदेश की पुष्टि करते हुए राहत को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित रखा, जिन्होंने अधिकरण से संपर्क किया था।

'उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ, यूपी राज्य एसएलपी के एक बैच में आया। 1995 के सीए नंबर 4438-42 में। सिविल अपीलों के इस बैच में इस न्यायालय के 2-न्यायाधीशों ने अपने आदेश दिनांक 23.3.1995 द्वारा कहा: "यह स्थापित कानून है कि सभी तदर्थ नियुक्तियों ने नियमों को समाप्त कर दिया है स्थायीता या वरिष्ठता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। वे नियमों के अनुसार अपनी नियमित नियुक्ति की तारीख से ही अधिकार प्राप्त करते हैं। "ऐसा घोषित करते हुए कानून ने उन अस्थायी डॉक्टरों की वरिष्ठता को प्रभावित किया, जिन्हें चयनित डॉक्टरों की तुलना में बहुत पहले नियुक्त किया गया था। हालांकि 2-जजों की बेंच ने एसएलपी (सी) संख्या 14480/92 में दिए गए 3-जजों की बेंच के फैसले पर ध्यान दिया, लेकिन इस फैसले पर आगे चर्चा नहीं की और न ही विशिष्ट शब्दों में उस फैसले को अलग/खारिज किया, लेकिन एक दृष्टिकोण लेने के लिए आगे बढ़ी। जो सीधे तौर पर 3 जजों की बेंच द्वारा लिए गए विचार के विपरीत था। 23.3.1995 के उस आदेश को उसी पीठ द्वारा 1995 के सीए संख्या 4438-42 में आईए संख्या 16-20 आदि में उसके बाद के आदेश दिनांक 26.7.1996 द्वारा संशोधित किया गया। इस आदेश के द्वारा, न्यायालय ने यह मानते हुए कि सेवानिवृत्त डॉक्टरों को मिलने वाले लाभों में खलल नहीं डाला जाना चाहिए, यह माना कि पीएससी के माध्यम से भर्ती किए गए डॉक्टरों और उन डॉक्टरों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता जिनकी सेवाएं नियमितीकरण नियमों के तहत समाहित की गई थीं, के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। उक्त नियमों का नियम 7, जो वास्तव में 3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के भी विपरीत था। 2-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने चयनित डॉक्टरों की इस दलील को भी बरकरार रखा कि उन्हें गैर-चयनित (अस्थायी डॉक्टरों) से कनिष्ठ नहीं

माना जा सकता है और राज्य सरकार को यहां ऊपर उल्लिखित नियमितीकरण नियमों के अनुसार पदोन्नति देने का निर्देश दिया। इस तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है कि इस न्यायालय की 2–न्यायाधीश पीठ के दो आदेश कुछ चयनित डॉक्टरों की नियुक्ति के संबंध में सेवा न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देशों की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील में थे और नहीं थे किसी भी याचिका के संबंध में जिसमें अस्थायी डॉक्टरों और चयनित डॉक्टरों के पारस्परिक अधिकार सीधे तौर पर मुद्दे में थे, इस न्यायालय की 3–न्यायाधीश पीठ द्वारा तय किए गए डॉ. माथुर के मामले के विपरीत।

उपर्युक्त मामले में इस न्यायालय की 2–न्यायाधीश पीठ द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की गई परिणामी कार्रवाई के कारण याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपरोक्त रिट याचिका को प्राथमिकता दी है । इस न्यायालय ने 24.4.1998 को इस मामले में 'नियम' जारी किया, और सुनवाई के दौरान, 4.2.1999 को इस न्यायालय की 3–न्यायाधीशों की पीठ ने यह आवश्यक महसूस किया कि वे सभी व्यक्ति जो इनमें निर्णय से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। रिट याचिकाओं को इन याचिकाओं के लंबित होने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, इसलिए, इसने यूपी राज्य को दो दैनिक समाचार पत्रों में एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि इन रिट याचिकाओं की सुनवाई इस न्यायालय के समक्ष की जा रही है और जिनकी वरिष्ठता होने की संभावना है। प्रभावित, इस न्यायालय के समक्ष आने और अपनी बात रखने के हकदार हैं, जिसमें वे सभी व्यक्ति भी शामिल हैं जो पहले के न्यायालय के आदेशों द्वारा शासित हैं। इस आशय का एक समान परिपत्र सभी जिला मुख्यालयों को भी भेजने का निर्देश दिया गया।

उपरोक्त प्रकाशन और परिपत्रों के अनुसरण में, पक्षकार/हस्तक्षेप के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे और इन्हें उपरोक्त रिट याचिकाओं के साथ आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

इसी संदर्भ में 3 जजों की बेंच और 2 जजों की बेंच के फैसलों के बीच विरोधाभास को देखते हुए इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है।

भले ही रिट याचिकाओं को अंतिम निपटान के लिए इस बड़ी बेंच के पास भेजा गया हो, हमारी राय है कि हमें शुरुआत में 3–न्यायाधीशों की पीठ और 2–न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों के बीच टकराव के सवाल पर निर्णय लेना चाहिए। बेंच, और इस तरह के संघर्ष का प्रभाव, यदि कोई हो, और फिर तय करें कि रिट याचिकाओं पर अंतिम रूप से इस बेंच द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए या नहीं। मामले के उस दृष्टिकोण में, हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को यह पता लगाने के लिए सीमित सीमा तक सुना है कि क्या 2–न्यायाधीशों की पीठ और 3–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बीच कोई विरोधाभास है और यदि हां, तो क्या है? 2–न्यायाधीशों की पीठ के दिनांक 23.3.1995 और 26.7.1996 के निर्णयों का प्रभाव।

रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया कि अस्थायी डॉक्टरों की वरिष्ठता की गिनती की तारीख के संबंध में डॉ. माथुर के मामले में इस न्यायालय की 3–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से संबंधित मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता था। किसी भी तरीके से, परिवर्तन किया गया या परिवर्तित किया गया जिससे डॉक्टरों के उस वर्ग को नुकसान हुआ, जिन्हें डॉ. माथुर के समान स्थान पर रखा गया था क्योंकि उस फैसले में न केवल डॉ. एचसी माथुर के अधिकारों की घोषणा की गई थी, बल्कि समान रूप से स्थित डॉक्टरों के वर्ग के अधिकारों की भी घोषणा की गई थी। उनका यह भी तर्क है कि डॉ. माथुर के मामले में नियमितीकरण नियमों के नियम 7 के आवेदन पर विचार किया गया था, और उच्च न्यायालय द्वारा इसे अनुपयुक्त माना गया था, जिसकी पुष्टि इस

न्यायालय की 3–न्यायाधीशों की पीठ ने की थी, इसलिए, 2–न्यायाधीशों की पीठ ने खंडपीठ यह नहीं मान सकती थी कि अस्थायी डॉक्टरों की वरिष्ठता की गणना करते समय उक्त नियम लागू होता है। यह तर्क बाध्यकारी उदाहरणों के सिद्धांत पर आधारित है जिसके लिए आवश्यक है कि किसी बड़ी पीठ के फैसले को खारिज नहीं किया जाना चाहिए या समन्वय पीठ से अलग नहीं होना चाहिए, कम ताकत वाली पीठ द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं। यह कहा गया है कि न्यायिक अनुशासन के अलावा, इस न्यायालय के निर्णयों ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि एक समन्वय पीठ या कम ताकत वाली पीठ किसी अन्य समन्वय पीठ या बड़ी ताकत वाली पीठ द्वारा पहले दिए गए निर्णय को खारिज नहीं कर सकती है। इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा गया:

भारत संघ और अन्य. आदि बनाम रघुबीर सिंह (मृत) एलआर द्वारा। आदि, [1989] 2 एससीसी 754 और प्रदीप चंद्र पारिजा और अन्य। बनाम प्रमोद चंद्र पटनायक और अन्य , [2002] 1 एससीसी 1। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि 2–न्यायाधीशों की पीठ का आदेश प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी किए बिना दिया गया था।

इसके विपरीत, प्रत्यार्थी–आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क है कि 3–न्यायाधीशों की पीठ और 2–न्यायाधीशों की पीठ (सुप्रा) द्वारा लिए गए विचारों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, वास्तव में, 2–न्यायाधीशों की पीठ के बाद के आदेश विरोधाभासी होने के बजाय स्पष्टीकरण की प्रकृति में अधिक हैं। हालाँकि, वे इस बात से सहमत हैं कि यदि कोई विरोधाभास है तो 2–न्यायाधीशों की पीठ के इस तरह के दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

अब हम इस पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या वास्तव में निर्णयों के दो सेटों के बीच कोई विरोधाभास है। इस प्रक्रिया में, हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि डॉ. माथुर के मामले में इस न्यायालय का निर्णय एक पुष्टिकरण निर्णय था जिसमें इस न्यायालय ने संक्षिप्त होते हुए भी एक तर्कसंगत आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा था। इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है जो डॉ. माथुर के मामले में इस न्यायालय के समक्ष अपील के अधीन था। डॉ. माथुर सहित उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं के उक्त बैच में, उच्च न्यायालय ने माना कि अस्थायी डॉक्टरों की नियुक्तियाँ उन मूल रिक्तियों के विरुद्ध की गई थीं जो डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण खाली हो गई थीं। यह भी माना गया कि पीएमएस–II के रूप में नियुक्त होने के लिए रिट याचिकाकर्ताओं की पात्रता विवाद में नहीं थी। इसने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास नियमित नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता है। अपने समक्ष उपलब्ध रिकॉर्ड से, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता मूल रिक्तियों के विरुद्ध काम कर रहे थे और उन्हें कभी भी तदर्थ नियुक्त व्यक्ति नहीं माना गया। यह भी माना गया कि केवल इस तथ्य से कि उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया था, उन याचिकाकर्ताओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से सेवा में निरंतरता के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, और बाद में नियमितीकरण से उनकी नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का अधिकार नहीं छीन लिया जाएगा। उनकी प्रारंभिक नियुक्ति. इन निष्कर्षों के आधार पर ही उच्च न्यायालय ने पीएमएस कैडर में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से अस्थायी डॉक्टरों की वरिष्ठता तय करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें वे सभी सेवा लाभ दिए जा सकें जो उनकी वरिष्ठता तय करने के बाद उन्हें मिलने थे। जब इस फैसले को इस न्यायालय के समक्ष लाया गया तो तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इसे बरकरार रखा। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया कि नियमितीकरण नियमों से उन्हें वह लाभ नहीं मिला। फिर भी इस न्यायालय ने माना कि वे डॉक्टर अपनी वरिष्ठता की गणना के उद्देश्य से प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से अपनी सेवा की गणना करने के हकदार थे। हमने

पहले ही देखा है कि इस निर्णय का बाद के मामलों में क्रमिक रूप से पालन किया गया है, जिनमें से एक कम से कम इस न्यायालय के समक्ष आया और इस न्यायालय के उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि की गई।

इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में, जैसा कि हमने पहले देखा था, 2–न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि नियमों के अनुसार की गई तदर्थ नियुक्तियाँ स्थायीता या वरिष्ठता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं और वे केवल अपनी नियुक्ति की तारीख से ही यह अधिकार प्राप्त करते हैं। नियमानुसार नियमित नियुक्ति। इसने आगे कहा था कि जबकि वे अस्थायी डॉक्टर जिन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और न्यायालय से निर्देश प्राप्त किए थे, वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से अपनी वरिष्ठता की गणना कर सकते हैं, अन्य, इसका मतलब है कि वे अस्थायी डॉक्टर जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है, लेकिन इसी तरह नियुक्त किए गए थे को नियमों के तहत उनके नियमितीकरण की तिथि से ही वरिष्ठता दी जा सकती है। इस प्रकार, 2–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में उपरोक्त संदर्भित टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि जबकि 3–न्यायाधीशों की पीठ ने वरिष्ठता की गणना करने के हकदार एक वर्ग के रूप में अस्थायी डॉक्टरों (डॉ. माथुर के समान) के अधिकार को बरकरार रखा है। अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से, बाद के फैसले से 2–न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है कि अस्थायी नियुक्त व्यक्ति अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे केवल अपने नियमितीकरण की तारीख से ही गिन सकते हैं। नियमितीकरण नियमावली का नियम 7. यह अस्थायी डॉक्टरों और चयनित डॉक्टरों के बीच विवाद में शामिल मुख्य मुद्दा है, हमारी राय में, 2–जजों की बेंच ने 3–जजों की बेंच द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सीधे तौर पर विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया है।

इसलिए, हमारे विचार के लिए प्रश्न यह है: यह कहां तक स्वीकार्य है?

बाध्यकारी मिसाल के सिद्धांत के सिद्धांत अब संदेह में नहीं हैं। यह इस न्यायालय द्वारा तय किए गए बड़ी संख्या में मामलों में परिलक्षित होता है। हमारे सामने मौजूद मुद्दे पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, हम इस न्यायालय के निम्नलिखित दो निर्णयों का उल्लेख करना चाहते हैं।

भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह (सुप्रा) के मामले में , इस न्यायालय की 5–न्यायाधीशों की पीठ ने पाठक, मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से बात करते हुए कहा कि इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा एक कानून की घोषणा दूसरे पर बाध्यकारी है। समान या कम संख्या में न्यायाधीशों की खंडपीठ। फैसले में आगे कहा गया है कि ऐसा निर्णय बाध्यकारी होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह पूर्ण न्यायालय या न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिया गया निर्णय हो। इस विषय पर चर्चा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, हम उस निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ को पुन: प्रस्तुत करना उचित समझते हैं जो इस प्रकार है:

"फिर कम संख्या में न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष उसी बिंदु को साकार करने वाले मामले के संबंध में एक खंडपीठ द्वारा सुनाए गए कानून के प्रभाव के संबंध में क्या स्थिति होनी चाहिए? इसमें कोई संवैधानिक या वैधानिक नुस्खा नहीं है मामला, और यह मुद्दा पूरी तरह से भारत में एक सदी से अधिक समय से बार–बार पुष्टि द्वारा पवित्र किए गए न्यायालयों के अभ्यास से नियंत्रित होता है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि एक बेहतर न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून में स्थिरता और निश्चितता को बढ़ावा देने के लिए, आदर्श शर्त यह होगी कि कानून के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए संपूर्ण न्यायालय को सभी मामलों में बैठना चाहिए, और इसी कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करता है। लेकिन न्यायालय के ध्यान की मांग करने वाले काम

की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, यह किया गया है भारत में अभ्यास और सुविधा के एक सामान्य नियम के रूप में यह आवश्यक पाया गया कि न्यायालय को डिवीजनों में बैठना चाहिए, प्रत्येक डिवीजन में न्यायाधीशों का गठन किया जाना चाहिए जिनकी संख्या न्यायिक आवश्यकता की तात्कालिकता, मामले की प्रकृति और उससे संबंधित किसी वैधानिक आदेश सहित निर्धारित की जा सकती है। , और ऐसे अन्य विचार से जो मुख्य न्यायाधीश, जिसमें ऐसा अधिकार परंपरा द्वारा हस्तांतरित होता है, सबसे उपयुक्त लग सकता है। विभिन्न डिवीजन बेंचों द्वारा कानून के बिंदुओं पर असंगत निर्णयों की संभावना से बचाव के लिए यह नियम विकसित किया गया है, ताकि कानून के विकास और इसकी समकालीन स्थिति में स्थिरता और निश्चितता को बढ़ावा दिया जा सके। एक डिविजन बेंच द्वारा बनाया गया कानून समान या उससे कम न्यायाधीशों की डिविजन बेंच पर बाध्यकारी माना जाता है। भारत में न्यायाधीशों की कई पीढ़ियों द्वारा इस सिद्धांत का पालन किया गया है। हम इस मुद्दे पर हाल के कुछ मामलों का उल्लेख कर सकते हैं। जॉन मार्टिन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य , [1975] 3 एससीसी 836 में, तीन न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने हराधन शाह बनाम पश्चिम बंगाल राज्य , [1975] 3 एससीसी 198, में घोषित कानून का पालन करना सही पाया। भूत नाथ मटे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य , [1974] 1 एससीसी 645 के मामले में पांच न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने दो न्यायाधीशों की एक खंडपीठ द्वारा फैसला सुनाया। फिर से इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण में , [1975] पूरक। एससीसी 1, बेग जे ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य , [1973] 4 एससीसी 225] मामले में माना कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ तेरह न्यायाधीशों की संविधान पीठ से बंधी थी। गणपति सीताराम बलवलकर बनाम महिला श्रीपाद मागे , [1981] 4 एससीसी 143 में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा कानून के एक बिंदु पर लिया गया दृष्टिकोण तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ के लिए बाध्यकारी था। न्यायालय। और मट्टूलाल बनाम राधे लाल में, [1974] 2 एससीसी 365, इस न्यायालय ने विशेष रूप से देखा कि जहां इस न्यायालय की दो अलग–अलग डिवीजन बेंचों द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण में सामंजस्य नहीं हो सका, वहां बड़ी संख्या में न्यायाधीशों की डिवीजन बेंच के फैसले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कम संख्या में न्यायाधीशों की एक खंडपीठ। इस न्यायालय ने आचार्य महाराजश्री नरेंद्रप्रसाईजी आनंदप्रसादजी महाराज बनाम गुजरात राज्य, [1975] 1 एससीसी 11 में भी यह व्यवस्था दी थी कि जहां दो अलग–अलग डिवीजन बेंचों में न्यायाधीशों की संख्या समान थी, वहां एक डिवीजन बेंच के लिए खुला नहीं था। दूसरे के विचारों की सत्यता या अन्यथाता का निर्णय करना। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड , [1985] 4 एससीसी 369 में इस सिद्धांत की फिर से पुष्टि की गई, जिसमें कहा गया कि जीत राम शिव कुमार बनाम हरियाणा राज्य , [1981] 1 एससीसी में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक डिवीजन बेंच थी। 11 मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स बनाम यूपी राज्य , [1979] 2 एससीसी 409 में दो न्यायाधीशों की पिछली डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न था, क्या प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत को बचाव का आह्वान करके पराजित किया जा सकता है। कार्यकारी आवश्यकता, और यह मानना कि ऐसा करना पूरी तरह से अस्वीकार्य था, बाद की पीठ द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की अच्छी तरह से स्वीकृत और वांछनीय प्रथा का संदर्भ दिया गया था जब विद्वान न्यायाधीशों ने पाया कि स्थिति में इस तरह के संदर्भ की आवश्यकता थी।" लगभग समान है पारिजा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की 5–न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले द्वारा व्यक्त विचार। उस मामले में, 2 विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने 3 विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया, इसलिए, सीधे संदर्भित किया गया मामले को पुनर्विचार के लिए 5 विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया। ऐसी स्थिति में, 5 न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि न्यायिक अनुशासन और औचित्य की मांग है कि 2 विद्वान न्यायाधीशों की पीठ को 3 विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पालन करना चाहिए। इस आधार पर, 5–जजों की बेंच ने बाध्यकारी मिसाल के सिद्धांत के आधार पर 2–जजों की बेंच द्वारा दिए गए संदर्भ में गलती पाई।

उपरोक्त निर्णयों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि इस न्यायालय ने भारत में न्यायिक प्रणाली के पदानुक्रमित चरित्र पर ध्यान दिया। यह भी माना गया कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून निश्चित, स्पष्ट और सुसंगत होना चाहिए। जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में कहा गया है, यह सामान्य ज्ञान है कि इस न्यायालय के अधिकांश निर्णय न केवल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पक्षों के अधिकारों पर निर्णय देते हैं और उनके बीच विवादों को हल करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि ऐसा करने में वे महत्वपूर्ण होते हैं। भविष्य के मामलों में बाध्यकारी सिद्धांत के रूप में कार्य करने वाले कानून की घोषणा। हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रशासन में बाध्यकारी मिसाल का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न्यायिक निर्णयों में निश्चितता और निरंतरता को बढ़ावा देता है। न्यायिक स्थिरता प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देती है, इसलिए, इस न्यायालय के निर्णयों में कानूनी सिद्धांतों के प्रतिपादन में निरंतरता की आवश्यकता है। उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने रघुबीर सिंह के मामले में माना कि इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा कानून की घोषणा समान या समान संख्या के न्यायाधीशों की डिवीजन बेंच पर बाध्यकारी है। कानून के इस प्रतिपादन को आगे बढ़ाते हुए, इस न्यायालय ने पारिजा (सुप्रा) के बाद के फैसले में कहा कि–

"लेकिन अगर दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ यह निष्कर्ष निकालती है कि तीन विद्वान न्यायाधीशों का पिछला फैसला इतना गलत है कि किसी भी परिस्थिति में इसका पालन नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए उचित रास्ता यह होगा कि वह मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दे। विद्वान न्यायाधीश कारण बता रहे हैं कि वह पहले के फैसले से सहमत क्यों नहीं हो सका। यदि, फिर, तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ भी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ का पिछला निर्णय गलत है, तो एक पीठ का संदर्भ दिया जाएगा पाँच विद्वान न्यायाधीश न्यायोचित हैं।"

(जोर दिया गया) हम रघुबीर सिंह और परीजा (सुप्रा) में उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के प्रति सम्मानजनक सहमति में हैं। उपर्युक्त मामलों में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम मानते हैं कि इस न्यायालय की 2–न्यायाधीशों की पीठ का दिनांक 23.3.1995 का निर्णय, जैसा कि उसी पीठ द्वारा 26.7.1996 के बाद के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है, सही कानून निर्धारित नहीं करता है। बड़ी बेंच के फैसले के विरोध में होना। यदि ऐसा है, तो उपरोक्त रिट याचिकाएं, जिनसे यह संदर्भ उत्पन्न हुआ है, पर दो विद्वान न्यायाधीशों की खंडपीठ के उन दो निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून के दायरे से बाहर निर्णय लेना होगा। इसलिए, हमारे विचार के लिए उठे मुद्दे पर निर्णय लेने के बाद, हम यही सोचते हैं कि इन रिट याचिकाओं को अब अंतिम निपटान के लिए तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

इस स्तर पर, उत्तरदाताओं की ओर से दिए गए तर्क को रिकॉर्ड करना आवश्यक है कि हमारे सामने रिट याचिकाकर्ताओं को डॉ. माथुर के समान नहीं रखा गया है, इसलिए, डॉ. माथुर के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का लाभ नहीं है। रिट याचिकाकर्ताओं पर लागू। उनका यह भी तर्क है कि डॉ. माथुर के मामले का निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के पहले के फैसले के विपरीत है। वी. डॉ. एमजे सिद्दीकी और अन्य , [1980] 3 एससीसी 174, इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि यहां रिट याचिकाकर्ताओं के दावे को डॉ. माथुर के मामले में 3–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से स्वतंत्र माना जाना चाहिए। इस स्तर पर, हमारे लिए यह कहना पर्याप्त है कि हम इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं और अन्य उत्तरदाताओं के परस्पर अधिकारों या डॉ. माथुर के मामले में 3–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की शुद्धता पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। यदि ऐसा कोई तर्क उठाया जाता है, तो उस पर पीठ द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जाएगा जो इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसलिए हम इन सवालों पर कोई राय व्यक्त नहीं

करते. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हम इन याचिकाओं में लंबित पक्षकार/हस्तक्षेप आवेदनों पर कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं और इन रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पीठ द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

ऊपर बताए गए कारणों से, हम मानते हैं कि इस न्यायालय के दिनांक 23.3.1995 और 26.7.1996 के सीए संख्या 4438–42/95 में 2–न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले कानून की सही घोषणा को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, जो इसके विपरीत है। 1992 की एसएलपी संख्या 13840 में 3–न्यायाधीशों की पीठ के दिनांक 24.11.1992 के फैसले के अनुसार, हम आगे निर्देश देते हैं कि इन याचिकाओं को अब तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निपटान के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। तदनुसार आदेश दिया गया।

याचिकाओं का उत्तर दिया गया।